

## मानव संसाधन शिक्षा व आर्थिक विकास



\*डॉ. आशा अग्रवाल \*\* डॉ. प्रतिभा परिहार

### शोधपत्र-अर्थशास्त्र

आर्थिक विकास कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि मानवीय उपक्रम है, अतः जब तक देश में अच्छे मानवीय संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे देश का तीव्र विकास नहीं हो सकता। मानवीय संसाधन के विकास से तात्पर्य, मानव की शिक्षा प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य पर व्यय किया जाना है जिसे मानव पूंजी निर्माण भी कहते हैं, हमारी आर्थिक नीति का दुखद पहलू यह है कि, हमने भौतिक पूंजी निर्माण के विकास पर तो ध्यान दिया परंतु मानवीय संसाधन के विकास की उपेक्षा की जिसके कारण ही वांछित आर्थिक विकास नहीं हो सका। यदि मानव पूंजी की कमी हो, तो भौतिक पूंजी का उत्पादकता, से उपयोग नहीं हो पाता। हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का ठीक से आंकलन नहीं कर पाते व बाजार की सही स्थितियों का विश्लेषण नहीं कर पाते न फलदायी शोध हो पाते हैं, वस्तुतः मानव संसाधन के गुण में सुधार किये बिना देश का आर्थिक विकास नहीं हो सकता है,। आज हम उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण, बाजार तंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं, जिनके पीछे हमारा प्रयोजन है कि देश की उत्पादकता में वृद्धि हो परंतु हमें यह नीति भूलना चाहिए की बाजार शक्तियां या प्रतिस्पर्धात्मक शक्तियां कोई जादू नहीं हैं जिसके कारण स्वतः मानवीय उद्यम शीलता और उत्पादकता में वृद्धि हो जायेगी।

उद्देश्य:— इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास (शुद्ध राष्ट्रीय आय) पर मानव पूंजी संघटको का अध्ययन करना है, जिसमें शिक्षा पर किये गये व्यय का आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है का अध्ययन किया गया है।

परिकल्पना:— प्रस्तुत शोध पत्र में यह परिकल्पना ली गई है कि भारत का आर्थिक विकास (शुद्ध राष्ट्रीय आय) को बढ़ाने में शिक्षा पर किया गया व्यय का प्रभाव समयावधि (1995 से 2000) के मध्य किस प्रकार रहा। इस परिकल्पना का अधिकार थियोडोर शुल्ज (1963 व 1988), अर्मत्य सेन (1973), विलम जालान (1912), मो. महबूब उल हक (1996), स्वामी नाथन और रावल (1999) एव नायक (1999) के विचार हैं,। जैसे प्रो. शुल्ज के अनुसार “सन् 1909 और 1929 के मध्य अमेरिका (यू.एस.ए.) कि संवृद्धि में भौतिक पूंजी का योगदान,

विद्यालयीन शिक्षा के योगदान से दो गुना अधिक था लेकिन सन् 1929 और 1957 के मध्य विद्यालयीन शिक्षा का योगदान भौतिक पूंजी से अधिक हो गया है।” अतः त्य सेन (1973) का मत है “कि भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों के लिए गरीब जनता को सुखी करने हेतु शिक्षा व स्वास्थ्य पर समान मात्रा में ध्यान देना अनिवार्य है।” इन विचारों के आधार पर राज्यवार शिक्षा का स्तर एवं आर्थिक विकास के मध्य जो तुलनात्मक अध्ययन किया गया वह निम्नानुसार है—

तालिका - 1

शिक्षा एवं आर्थिक विकास का राज्यवार तुलनात्मक अध्ययन (सन् 1995 से 2005 तक)

उच्च (High)	हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर		
मध्य निम्न	गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु हरियाणा, पंजाब,	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान पश्चिम बंगाल,	आसाम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा बिहार, उत्तर प्रदेश

Source :- Computed

उपरोक्त तालिका यह प्रदर्शित करती है कि हिमाचल एवं जम्मू-कश्मीर ऐसे राज्य हैं जहां शिक्षा पर किया गया व्यय उच्च (भूपही) होने के साथ-साथ आर्थिक विकास भी उच्च रहा जबकी विहार एवं उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर निम्न व्यय का स्तर एवं निम्न आर्थिक विकास का स्तर है। गुजरात, केरल, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जिनका शिक्षा पर किया गया व्यय मध्य स्तर का था, पर आर्थिक विकास का स्तर उच्च रहा। मध्य प्रदेश, असम एवं उड़ीसा में शिक्षा के विकास पर किया गया व्यय का स्तर मध्य था एवं आर्थिक विकास का स्तर भी मध्य रहा। हरियाणा एवं पंजाब दो ऐसे राज्य हैं जहां आर्थिक विकास का स्तर उच्च रहा जबकी शिक्षा पर किया गया व्यय का स्तर निम्न है इसका कारण ये दोनों राज्यों का शुद्ध राष्ट्रीय आय में कृषि का बड़ा योगदान रहा है। हरियाणा एवं पंजाब भले ही अपवाद वाले क्षेत्र हैं, किन्तु अन्य राज्यों के आर्थिक विकास को देखे तो शिक्षा के विकास को नहीं नकारा जा सकता है।

\* विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र, शासकीय नेहरू पी.जी. कॉलेज बुढ़ार ( म.प्र )

\*\* प्राध्यापक अर्थशास्त्र, विभाग नेहरू पी.जी. कॉलेज बुढ़ार ( म.प्र. )

उर्पयुक्त निर्देशो से स्पष्ट है कि शुद्ध राष्ट्रीय आय बढ़ाने में शिक्षा वा स्वास्थ्य जैसे समाजिक घटक धनात्मक असर डालते हैं सुधारों के उपरांत इन दोनों चरों की आर्थिक विकास में अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है। शिक्षा के क्षेत्र में किया गया विनियोजन आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक का कार्य करेगा, आर्थिक विकास की गति को मजबूती प्रदान करेगा जिसके निम्न सकारात्मक परिणाम सामने आयेंगे –

- शिक्षित मानव कुशल प्रबंधन, मूल्यांकन एवं मानीटरिंग करेगा जिससे उपलब्ध संसाधनों का उचित तरीके से प्रयोग होगा। समाज के कमजोर, आसुरक्षित वर्ग के आर्थिक विकास के प्रक्रिया में अनुकूल एवं सुरक्षात्मक कवच का काम करेगा।

- भारत जैसे विकासशील देशों में मानवीय संसाधनों से संबंधित दो भिन्न किन्तु परस्पर संबंधित समस्याएँ विद्यमान हैं, प्रथम श्रम के अतिरेक की उपस्थिति व द्वितीय औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रशिक्षित कुशल श्रम की कमी। वास्तव में अतिरेक श्रम शक्ति की उपस्थिति काफी हद तक प्रशिक्षित कुशलताओं की कमी के परिणाम स्वरूप है। अतः यदि इन समस्याओं का प्रभावी हल ढूँढना है तो इसका एक मात्र हल मानव पूंजी निर्माण है।

- यद्यपि हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत मानव संसाधन विकास को प्राथमिकता दी गई है पर देश के मानवीय

संसाधनों के विकास कार्यक्रमों के प्रति और भी अधिक जागरूक होना पड़ेगा तथा आगामी योजनाओं में इन्हे सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी तभी देश विकास के विभिन्न सोपानों को प्राप्त करने में सफल हो सकेगा।

- संपूर्ण अध्ययन के विश्लेषणत्मक अध्ययन से निश्चित है कि कुल राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक विकास का पर्याय है एवं आर्थिक विकास समाजिक क्षेत्र में होने वाले मानव संसाधन शिक्षा जैसे तत्वों का पर्याय है। अतः स्पष्ट है कि हमारे देश में मानव संसाधन के विकास की दिशा में निवेश करने के प्रति उदासीनता दिखाई गई है, हमें यह समझ लेना चाहिए कि राष्ट्र और राष्ट्रीय संपत्ति के संपूर्ण विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने के साथ-साथ मानव संसाधन पर भी निवेश करना जरूरी है। आज जबकी पूरी दुनिया एक गांव बन गई है, संचार जाल विछा हुआ है, खुले व्यापार ने विस्तृत बाजार उपलब्ध करवा दिया है तब मानव संसाधन का विकास किये बिना कोई भी राष्ट्र अपनी जड़े मजबूत नहीं कर सकता है, हमारी आर्थिक नीतिकारों और निवेश निर्धारित करने वाली संस्थाओं को इस तथ्य अर्थात् मानव संसाधन की शक्ति की वास्तविकता को अनदेखा नहीं करना चाहिए। यह आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण की अनिवार्यता भी है।

## सन्दर्भ ग्रन्थ

- Das A (2001) Socio – Economic Development in India, Development & society.
- Sen A (1997) Indian Development Selected Regional perspective .
- आर्थिक समीक्षा (2005.2006) भारत सरकार, नई दिल्ली,
- प्रतियोगिता दर्पण (2008) पृष्ठ 51 जन गडना रिपोर्ट 2001
- कादर, ए.एस. (2000) जन संख्या एवं मानव संसाधन विकास, योजना, अगस्त p.p 20–24.